

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94

email: doonvalley_news@yahoo.com

Website: dunvalleymail.com

डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

अंकिता हत्याकांड : न्याय की लड़ाई पर राजनीतिक 'बवंडर' भारी

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग अब केवल अदालत, जांच और अभियोजन तक सीमित नहीं रह गई है। यह मामला प्रदेश की राजनीति के केंद्र में है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक, विपक्ष के राजनीतिक मंचों से लेकर सत्तारूढ़ भाजपा के जवाबी हमलों तक, अंकिता के नाम पर सियासी संघर्ष तेज होता जा रहा है। सवाल यह है कि जिस मामले में जनता निष्पक्ष जांच, दोषियों को सजा और कथित वीआईपी की भूमिका पर स्पष्टता चाहती है, उसमें न्याय की मांग और राजनीतिक लाभ की कोशिशों के बीच की रेखा लगातार धुंधली क्यों पड़ रही है?

अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के लिए महज एक आपराधिक मामला नहीं, बल्कि महिला सुरक्षा, सत्ता की जवाबदेही और व्यवस्था पर जनता के भरोसे की कसौटी बन चुका है। यही कारण है कि मामले से जुड़ा कोई भी घटनाक्रम राजनीतिक प्रतिक्रिया पैदा करता है। कांग्रेस इसे सरकार को घेरने के अवसर के रूप में देख रही है, जबकि भाजपा जांच और कानूनी कार्रवाई का हवाला देकर विपक्ष पर मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाती रही है। इस टकराव में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए राजनीतिक दलों की घोषणाएं ठोस नतीजों में कितनी बदल रही हैं?

मामले को लेकर अंकिता के माता-पिता की मांगों ने राजनीतिक बहस को

और तेज किया है। कथित वीआईपी की भूमिका की जांच और सीबीआई जांच को लेकर उठ रहे सवालों ने प्रदेश की राजनीति में नए सिरे से हलचल पैदा की है। अंकिता के माता-पिता की आवाज को राजनीतिक बयानबाजी में सीमित नहीं किया जा सकता। उनकी मांगों का परीक्षण तथ्यों, साक्ष्यों और कानून के आधार पर होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोपों का निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही निकलना चाहिए। दूसरी ओर, विपक्ष का तर्क है कि जब तक मामले से जुड़े सभी सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तब तक जनता की शंकाएं दूर नहीं होंगी। कांग्रेस इस मुद्दे को सरकार की जवाबदेही से जोड़ रही है। न्याय यात्रा और विरोध प्रदर्शनों के जरिए वह अंकिता प्रकरण को जनभावनाओं से जोड़ने की कोशिश में है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या यह आंदोलन न्याय की मांग को निर्णायक दिशा दे पाएगा या चुनावी राजनीति के शोर में उलझकर रह जाएगा?

सत्तारूढ़ भाजपा के सामने चुनौती केवल विपक्ष के आरोपों का जवाब देने की नहीं है। उसे यह भी सुनिश्चित करना है कि जनता के मन में उठ रहे सवालों का तथ्यपरक और विश्वसनीय समाधान सामने आए। सरकार और भाजपा की ओर से जांच तथा कानूनी कार्रवाई का हवाला दिया जाता रहा है, लेकिन किसी संवेदनशील मामले में केवल कार्रवाई गिनाना पर्याप्त नहीं होता। जनता यह जानना चाहती है कि जांच के निष्कर्ष क्या हैं, न्यायिक प्रक्रिया



किस दिशा में आगे बढ़ी है और जिन सवालों को लेकर असंतोष है, उनका जवाब किस आधार पर दिया जा रहा है।

◆ कानूनी कार्रवाई अपनी जगह, सियासी संग्राम अपनी जगह
◆ विस चुनाव से पहले राजनीति का बड़ा मुद्दा बना मामला
◆ न्याय की मांग और राजनीतिक लाभ की कोशिशें धुंधली

भाजपा यदि विपक्ष पर राजनीतिक रोटियां सेंकने का आरोप लगाती है, तो उसे भी यह समझना होगा कि अंकिता का मामला किसी एक दल की प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। यह उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने और व्यवस्था के प्रति विश्वास बनाए रखने का सवाल है। इसी तरह विपक्ष को भी आरोपों को राजनीतिक हथियार बनाने के बजाय तथ्यों और प्रमाणों के आधार

पर अपनी बात रखनी होगी।

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के बीच अंकिता भंडारी हत्याकांड का राजनीतिक महत्व बढ़ना तय है। कांग्रेस इसे महिला सुरक्षा और सरकार की जवाबदेही से जोड़कर भाजपा को घेरने की कोशिश करेगी। भाजपा की रणनीति विपक्ष के आरोपों को राजनीतिक अवसरवाद बताकर अपने पक्ष को मजबूत करने की होगी। दूसरे राजनीतिक दल भी जनभावनाओं से जुड़े इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं।

लेकिन चुनावी राजनीति में इस मामले का इस्तेमाल करने और न्याय की मांग को जीवित रखने में अंतर है। यदि राजनीतिक दलों की सक्रियता केवल बयान, आरोप-प्रत्यारोप, धरना और प्रदर्शन तक सीमित रहती है, तो इससे

जनता की बेचौनी कम होने के बजाय बढ़ सकती है। इसके विपरीत, यदि राजनीतिक दबाव का परिणाम पारदर्शिता, जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को मजबूत करने के रूप में सामने आता है, तो यह लोकतांत्रिक राजनीति की सार्थक भूमिका होगी।

अंकिता भंडारी हत्याकांड ने उत्तराखंड की राजनीति को एक असहज सवाल के सामने खड़ा कर दिया है। क्या राजनीतिक दल इस मामले को न्याय की मांग के रूप में देखेंगे या इसे चुनावी जीत-हार का औजार बना देंगे? क्या सत्ता पक्ष जनता की शंकाओं का जवाब तथ्यों से देगा और क्या विपक्ष अपने आरोपों को प्रमाणों के आधार पर आगे बढ़ाएगा? इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक बयानबाजी से अलग रखते हुए चलना चाहिए। जांच से जुड़े तथ्यों, अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और न्यायिक निष्कर्षों को ही निर्णायक महत्व मिलना चाहिए।

अंकिता के नाम पर राजनीति हो रही है या राजनीति के दबाव से न्याय की मांग मजबूत हो रही है? इसका फैसला नारों से नहीं, नतीजों से होगा। उत्तराखंड की जनता को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से आगे बढ़कर पारदर्शी जवाब, जवाबदेही और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा चाहिए।

2027 के चुनाव में राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर अपनी-अपनी परीक्षा देनी होगी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष चुनाव नहीं, अंकिता को न्याय दिलाने का सवाल है।

नार्को टेस्ट से पहले उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी क्यों: कांग्रेस

हमारे संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अंकिता भंडारी हत्याकांड में उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी की टाइमिंग और कथित वीआईपी की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। प्रेस वार्ता को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष सुजाता पॉल और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने संबोधित किया।

सीबीआई जांच शुरू होने के बाद उर्मिला सनावर से पूछताछ हुई और सीबीआई की टीम उनके सहारनपुर स्थित आवास पर पहुंची। 23 अक्टूबर को उर्मिला सनावर और पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौर ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए देहरादून कोर्ट में सहमति दी थी। अगली कानूनी प्रक्रिया 26 अक्टूबर को आगे बढ़नी थी, लेकिन 24 अक्टूबर की



रात एक अलग शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ और 25 अक्टूबर को उर्मिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सुजाता पॉल ने सवाल उठाया कि जब उर्मिला नार्को टेस्ट के लिए सहमति दे चुकी थीं और कथित वीआईपी से जुड़े गंभीर आरोपों में बड़े नामों का उल्लेख कर रही थीं, तो ठीक

अगली पेशी से पहले उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? क्या इस कार्रवाई से नार्को टेस्ट की प्रक्रिया प्रभावित या विलंबित होगी? पहले भी इसी विवाद से जुड़ी शिकायत और गैर-जमानती वारंट की बात सामने आई थी। ऐसे में पुरानी और नई कार्रवाई के बीच अंतर तथा गिरफ्तारी के समय को लेकर पुलिस को स्पष्ट

जवाब देना चाहिए।

सुजाता पॉल ने कहा कि उर्मिला ने अपने बयानों में कथित वीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम और उनके वरिष्ठ नेताओं से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों की सत्यता जांच का विषय है। सीबीआई को स्पष्ट करना चाहिए कि इन बयानों, ऑडियो रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच कहाँ तक पहुँची है। क्या कथित वीआईपी को लेकर किसी तरह के दबाव या मामले में समझौता कराने की कोशिश हुई? यदि ऐसा कोई आरोप या साक्ष्य सामने आया है, तो उसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को दोषी मानने से पहले तथ्य सामने आना जरूरी है, लेकिन गंभीर सवालों को अनुत्तरित भी नहीं छोड़ा जा सकता। महिला कांग्रेस की

प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि अंकिता भंडारी के माता-पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लगातार दर-दर भटक रहे हैं। परिवार की पीड़ा और उत्तराखंड की जनता में इस मामले को लेकर व्याप्त आक्रोश का सम्मान करते हुए सरकार और जाँच एजेंसियों को पारदर्शी जवाब देना चाहिए। जब परिवार लंबे समय से कथित वीआईपी का नाम लेकर निष्पक्ष जाँच की माँग कर रहा है, तो अब तक इस पहलू पर क्या प्रगति हुई है, यह सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। दुष्यंत कुमार गौतम की नियुक्ति और इस प्रकरण से जुड़े सवालों के बीच क्या किसी तरह का दबाव या समझौता कराने का प्रयास हुआ, इस बारे में भी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जाँच होनी चाहिए।

दून वैली मेल

संपादकीय

पहाड़ों की चिंता किसे ?

उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी प्रकृति का सौंदर्य है, लेकिन इस सौंदर्य के पीछे छिपी चुनौतियां हमारी विकास नीति की असलियत भी उजागर करती हैं। ऊंची चोटियों पर बर्फ की चादर बिछते ही पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। सोशल मीडिया पर हिमालय की तस्वीरें छा जाती हैं। पर्यटकों की आमद, होटल कारोबार और शीतकालीन पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसी हिमालय में बसे उन गांवों का क्या, जहां बर्फबारी के साथ रास्ते बंद होने, बिजली-पानी की आपूर्ति बाधित होने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए संघर्ष बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है? सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड के लिए हिमालय केवल पर्यटन का आकर्षण है या उस जीवन का आधार भी, जिसे बचाने की जिम्मेदारी सरकार और समाज दोनों की है? विडंबना देखिए कि पहाड़ की बर्फ को हम पर्यटन की संभावनाओं में गिनते हैं, लेकिन पहाड़ के लोगों की कठिनाइयों को अक्सर मौसम की सामान्य समस्या मानकर छोड़ देते हैं। पर्यटकों के लिए बर्फबारी रोमांच है, तस्वीर है और कुछ दिनों की छुट्टी का आनंद है। स्थानीय निवासियों के लिए यही बर्फबारी कई बार आजीविका, आवागमन, स्वास्थ्य सेवाओं और बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी गंभीर चुनौती बन जाती है। पर्यटन से होने वाली कमाई का गुणगान करने वाले तंत्र को यह भी बताना चाहिए कि बर्फ से घिरे दूरस्थ गांवों तक जरूरी सेवाएं पहुंचाने की तैयारी कितनी है। हिमालय की सुंदरता पर मुग्ध होना आसान है, उसकी कठिनाइयों की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल। उत्तराखंड की राजनीति और विकास की बहस में यही विरोधाभास बार-बार सामने आता है। एक तरफ पहाड़ों को पर्यटन प्रदेश बनाने के दावे हैं, दूसरी तरफ सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता अब भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यदि बर्फबारी के दौरान सड़क संपर्क टूटने, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित होने या आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच में कठिनाई की आशंका बनी रहती है, तो यह केवल मौसम की समस्या नहीं, बल्कि हमारी तैयारियों की परीक्षा है। बर्फबारी के साथ उत्तराखंड के औली, मुनस्यारी, चोपता और दूसरे हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों का आकर्षण बढ़ना स्वाभाविक है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है और पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है। लेकिन क्या सरकार ने पर्यटन के इस संभावित उछाल के साथ जुड़ी पर्यावरणीय और प्रशासनिक चुनौतियों का पर्याप्त आकलन किया है? क्या संवेदनशील क्षेत्रों में वाहनों, निर्माण गतिविधियों, कचरे और पर्यटकों की भीड़ को नियंत्रित करने की व्यवस्था प्रभावी है? पर्यटन का अर्थ केवल अधिक पर्यटक, अधिक होटल और अधिक कारोबार नहीं हो सकता। यदि पर्यटन की कीमत स्थानीय पारिस्थितिकी को चुकानी पड़े, यदि कचरे का बोझ पहाड़ों पर बढ़ता जाए और यदि प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव अनियंत्रित हो जाए, तो यह विकास नहीं, भविष्य की समस्याओं को आमंत्रित करना है। हिमालय कोई ऐसा उपभोक्ता उत्पाद नहीं, जिसका इस्तेमाल करके उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाए। यह एक संवेदनशील प्राकृतिक व्यवस्था है, जिसके साथ खिलवाड़ का नुकसान आने वाली पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ सकता है। हिमालय में बर्फबारी के स्वरूप, तापमान और वर्षा में होने वाले बदलावों पर वैज्ञानिक निगरानी आज पहले से अधिक महत्वपूर्ण है। किसी एक बर्फबारी को जलवायु परिवर्तन का निर्णायक प्रमाण नहीं कहा जा सकता, लेकिन बदलते मौसम के दीर्घकालिक रुझानों को नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं है। ग्लेशियरों, हिमपात, जल स्रोतों और पर्वतीय पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले प्रभावों का नियमित अध्ययन जरूरी है। विडंबना यह है कि हिमालय के भविष्य पर चिंता जताने के लिए हम अक्सर किसी बड़ी आपदा का इंतजार करते हैं। आपदा आती है तो बैठकों, सर्वेक्षणों और राहत घोषणाओं का दौर शुरू होता है। कुछ समय बाद वही पुरानी व्यवस्थाएं, वही कमजोरियां और वही लापरवाहियां फिर सामने आने लगती हैं। मौसम खराब होने पर केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ाने या पर्यटन कारोबार को नुकसान से बचाने की चिंता पर्याप्त नहीं है। लोगों को जोखिम भरे मार्गों पर जाने से रोकना, वास्तविक स्थिति की जानकारी देना और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। प्रकृति के सामने मनुष्य की सीमाएं हैं। शासन की समझदारी इसी में है कि वह इन सीमाओं को पहचाने और लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे। इसके साथ ही, विकास के नाम पर पहाड़ों में होने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, भूगर्भीय संवेदनशीलता और प्राकृतिक जल निकासी पर पड़ने वाले प्रभावों की गंभीर समीक्षा होनी चाहिए। हर सड़क, हर भवन और हर पर्यटन परियोजना का मूल्यांकन केवल आर्थिक लाभ से नहीं किया जा सकता। पहाड़ों की भौगोलिक परिस्थितियों की अनदेखी करके किया गया विकास अंततः उन्हीं लोगों के लिए जोखिम बढ़ा सकता है, जिनके जीवन को सुगम बनाने के दावे किए जाते हैं। उत्तराखंड की असली पूंजी उसकी हिमालयी चोटियां, नदियां, जंगल, जैव विविधता और उन पर आधारित जीवन-पद्धति है। यदि यही प्राकृतिक आधार कमजोर पड़ता है, तो पर्यटन की चमक भी ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकती। इसलिए सरकार को शीतकालीन पर्यटन की योजनाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय रोजगार, आपदा प्रबंधन और सीमांत गांवों की जरूरतों को एक ही नीति का हिस्सा बनाना होगा। हिमालय की चोटियों पर बर्फ की सफेदी तभी सुकून देगी, जब उसके नीचे बसे गांवों में जिंदगी असुरक्षित और असहाय नहीं होगी। उत्तराखंड को तय करना है कि उसे केवल बर्फ से ढकी चोटियों की तस्वीरें बेचने वाला पर्यटन प्रदेश बनना है या प्रकृति, आजीविका और मानवीय गरिमा के बीच संतुलन कायम करने वाला पर्वतीय राज्य। हिमालय का भविष्य प्रचार से नहीं, दूरदर्शी नीति, संवेदनशील शासन और पर्यावरण के प्रति ईमानदार प्रतिबद्धता से सुरक्षित होगा।

खरगे की टिप्पणी से तूफान

कार्यालय संवाददाता
देहरादून/नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत पिता को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की विवादित टिप्पणी ने देश की राजनीति में नया बवंडर खड़ा कर दिया है। बिहार की राजधानी पटना में दिए गए बयान के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीतिक मर्यादा लांघने का आरोप लगाते हुए मोर्चा खोल दिया है। भाजपा ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। वहीं, कांग्रेस ने खरगे के बयान का बचाव करते हुए दावा किया कि उनकी टिप्पणी को संदर्भ से अलग करके पेश किया जा रहा है। इस घटनाक्रम ने भाजपा और कांग्रेस के बीच पहले से जारी राजनीतिक टकराव को और तीखा कर दिया है।

यह विवाद रविवार को पटना में बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान शुरू हुआ। अपने संबोधन में खरगे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर निशाना साध रहे थे। इसी दौरान श्रोताओं के बीच से एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री के सत्ता से नहीं जाने की बात कही। जवाब में खरगे ने प्रधानमंत्री के पिता का उल्लेख करते हुए विवादित टिप्पणी कर दी। इसके बाद कार्यक्रम में हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। खरगे की टिप्पणी सामने आते ही भाजपा ने इसे राजनीतिक शालीनता और सार्वजनिक जीवन की मर्यादा के खिलाफ बताया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस राजनीतिक मुद्दों पर प्रधानमंत्री

को घेरने के बजाय व्यक्तिगत टिप्पणियों का सहारा ले रही है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने बयान को कांग्रेस की वैचारिक कमजोरी से जोड़ते हुए इसकी आलोचना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित भाजपा के अन्य नेताओं ने भी खरगे की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई और माफी की मांग की।

भाजपा इस विवाद को केवल एक बयान तक सीमित नहीं रखना चाहती। पार्टी इसे कांग्रेस की राजनीतिक संस्कृति और

◆राजनीतिक विरोध की मर्यादा पर छिड़ गई है बहस
◆भाजपा ने मांगा खरगे और राहुल गांधी से माफीनामा
◆कांग्रेस ने टिप्पणी का अलग अर्थ बताते किया बचाव

प्रधानमंत्री के प्रति उसके रवैये से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है। देशव्यापी विरोध के ऐलान से साफ है कि भाजपा इस मुद्दे को व्यापक राजनीतिक बहस में बदलना चाहती है। भाजपा का तर्क है कि लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की नीतियों, फैसलों और कार्यशैली की कठोर आलोचना की जा सकती है, लेकिन राजनीतिक बहस में दिवंगत परिजनों को घसीटना उचित नहीं है। पार्टी ने खरगे के साथ राहुल गांधी से भी माफी मांगने की मांग उठाई है।

दूसरी ओर, कांग्रेस ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि

खरगे की टिप्पणी को उसके संदर्भ में समझा जाना चाहिए। पार्टी की ओर से दावा किया गया कि कार्यक्रम के दौरान खरगे के दिवंगत पिता को लेकर भी अपमानजनक टिप्पणी की गई थी और खरगे की प्रतिक्रिया को प्रधानमंत्री के वैचारिक आधार के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का उल्लेख करते हुए अपने अध्यक्ष के बयान का बचाव किया। हालांकि, कांग्रेस के इस बचाव के बावजूद विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। सार्वजनिक मंच पर इस्तेमाल की गई भाषा अब पार्टी के लिए राजनीतिक असहजता का कारण बन गई है। सवाल यह भी है कि क्या कांग्रेस इस विवाद से ध्यान हटाकर बेरोजगारी, महंगाई, मतदाता सूची पुनरीक्षण और चुनावी प्रक्रिया जैसे मुद्दों पर अपनी राजनीतिक लड़ाई को केंद्रित रख पाएगी?

इस विवाद का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि भाजपा और कांग्रेस के बीच संघर्ष अब नीतियों और चुनावी आरोपों से आगे बढ़कर सार्वजनिक भाषा और राजनीतिक आचरण तक पहुंच गया है। भाजपा को इस मुद्दे के जरिए कांग्रेस पर हमला करने का अवसर मिला है, जबकि कांग्रेस इसे बयान के संदर्भ और राजनीतिक प्रतिक्रिया के आधार पर समझाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बुनियादी सवाल दोनों दलों के सामने है कि क्या राजनीतिक विरोध की कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए?

►► शेष पृष्ठ 7 पर

न्याय यात्रा के नाम पर राजनीतिक ‘ढोंग’

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही सियासी संघर्ष सड़क पर उतर आया है। कांग्रेस की उत्तराखंड न्याय यात्रा को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल दिया है। भाजपा कांग्रेस के आंदोलन को जनन्याय की लड़ाई के बजाय राजनीतिक ढोंग करार दे रही है। सत्तारूढ़ दल का आरोप है कि कांग्रेस जनता के मुद्दों के समाधान के लिए नहीं, बल्कि चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए यात्रा और विरोध प्रदर्शनों का सहारा ले रही है। दूसरी ओर, कांग्रेस सरकार को महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं के मुद्दों पर घेरने में जुटी है। इस टकराव ने प्रदेश की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा कर दिया हैक्यूँक्या न्याय यात्रा कांग्रेस के लिए जनसमर्थन जुटाने का माध्यम बनेगी या भाजपा के हमलों के बीच उसकी राजनीतिक परीक्षा बनकर रह जाएगी?

कांग्रेस ने न्याय यात्रा के जरिए धामी सरकार को जनता के सवालों के कठघरे में खड़ा करने की रणनीति अपनाई है। पार्टी अंकित भंडारी हत्याकांड सहित विभिन्न मुद्दों को उठाकर सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर रही है। कांग्रेस का प्रयास है कि इन सवालों को गांवों, कस्बों और शहरों तक पहुंचाकर सरकार के खिलाफ जनमत तैयार किया जाए। भाजपा इस रणनीति को कांग्रेस की चुनावी कवायद के रूप में पेश कर रही है। पार्टी का तर्क है कि जनता के बीच सक्रियता दिखाने और वास्तव में जनता

के लिए संघर्ष करने में अंतर होता है। भाजपा के मुताबिक, कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि जिन मुद्दों को लेकर वह आज सड़क पर उतर रही है, उनके समाधान के लिए उसका अपना राजनीतिक दृष्टिकोण और ठोस कार्ययोजना क्या है।

हालांकि, कांग्रेस की यात्रा को केवल राजनीतिक ढोंग बताने से उन सवालों का

◆गैरसैंण तक सरकार को घेरने में जुटी कांग्रेस
◆भाजपा ने उठाए आंदोलन की मंशा पर सवाल
◆2027 के चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप तेज

महत्व समाप्त नहीं हो जाता, जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सत्ता से सवाल पूछना है। असली कसौटी यह है कि कांग्रेस अपने आरोपों को कितने ठोस तथ्यों के साथ जनता के सामने रखती है और भाजपा उनका कितना प्रभावी जवाब देती है। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों प्रमुख दलों की रणनीति स्पष्ट होती जा रही है। कांग्रेस जनसमस्याओं और सरकार की कथित विफलताओं को चुनावी विमर्श का केंद्र बनाना चाहती है। भाजपा दूसरी ओर विपक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल उठाकर उसके आंदोलन की धार कमजोर करने की कोशिश कर रही है।

अंकित भंडारी प्रकरण इस राजनीतिक संघर्ष का संवेदनशील पक्ष है। कांग्रेस इस

मामले में उठ रहे सवालों और न्याय की मांग को लेकर सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। भाजपा के सामने चुनौती है कि वह विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के साथ जनता के बीच मौजूद शंकाओं का भी तथ्यात्मक समाधान प्रस्तुत करे। यही स्थिति बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास से जुड़े सवालों पर भी है। यदि कांग्रेस इन मुद्दों को केवल भाषणों तक सीमित रखती है, तो भाजपा को उसके आंदोलन पर सवाल उठाने का अवसर मिलेगा। लेकिन यदि सरकार विपक्ष के हर सवाल को राजनीतिक स्टंट बताकर खारिज करती है, तो उसे भी जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

भाजपा कांग्रेस की न्याय यात्रा को राजनीतिक ढोंग बता रही है, लेकिन इस आरोप की राजनीतिक उपयोगिता तभी तक है, जब तक पार्टी अपने पक्ष में ठोस तथ्य और उपलब्धियां सामने रख सके। केवल विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाने से बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार और स्थानीय समस्याओं से जुड़े सवाल खत्म नहीं होंगे। इसी तरह कांग्रेस के लिए भी यात्रा की सफलता भीड़, नारों और राजनीतिक भाषणों से तय नहीं होगी। उसे यह साबित करना होगा कि वह जनसमस्याओं को लेकर लगातार संघर्ष करने और उनका व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम है। जनता के सामने केवल सरकार की आलोचना नहीं, बल्कि वैकल्पिक नीतियों और कार्ययोजना का

►► शेष पृष्ठ 7 पर

हिम तेंदुए के संरक्षण के प्रति किया जागरूक

उत्तरकाशी(आरएनएस)। विश्व हिम तेंदुआ दिवस पर जिले में वन विभाग की ओर से विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। हर्षिल के झाला क्षेत्र से लेकर गोविंद वन्यजीव विहार के नैटवाड़, सांकरी और दौणी तक विद्यार्थियों व स्थानीय लोगों को हिम तेंदुए के संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया।हिमालयी जैव विविधता में हिम तेंदुए की भूमिका और हिम प्राकृतिक आवास बचाने के प्रति लोगों को जागरूक किया गया।

गंगोत्री रेंज के तहत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय झाला और राजकीय प्राथमिक विद्यालय झाला में गोष्ठी आयोजित की गई। इसके बाद वन क्षेत्राधिकारी यशवंत चौहान की अगुवाई में विद्यालय से झाला बाजार तक जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान प्रवेश राणा, राजवीर रावत, जूनियर हाईस्कूल के उमेश, राजीव नयन, दीपक नौटियाल, अंजली रावत, जगिया आर्य, अनिरुद्ध बिष्ट आदि मौजूद थे। वन विश्राम भवन हर्षिल में भी हिम तेंदुए के संरक्षण, सुरक्षा और पर्यटन पर इसके प्रभाव को लेकर गोष्ठी की गई। वहीं, गोविंद वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान की ओर से नैटवाड़, सांकरी और दौणी के विद्यालयों में प्रश्नोत्तरी और पोस्टर प्रतियोगिताएं कराई गई। कहा गया कि वन विभाग के वर्ष 2०23 के आकलन के अनुसार गोविंद वन्यजीव विहार क्षेत्र में सात हिम तेंदुए दर्ज किए गए हैं। उप निदेशक निधि सेमवाल ने बताया कि हिम तेंदुआ हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में शीर्ष शिकारी के रूप में जैव विविधता का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेंज अधिकारी गौरव अग्रवाल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आवासों में कमी और मानवीय हस्तक्षेप इसके संरक्षण के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं।

रानीपोखरी में उपखनिज निकासी शुरु

ऋषिकेश(आरएनएस)। उत्तराखंड वन विकास निगम की ओर से खनन सत्र 2०26–27 के लिए जाखन–०1 उपखनिज लॉट के रानीपोखरी निकासी गेट से निकासी कार्य शुरू कर दिया गया है। निगम की प्रबंध निदेशक नीना ग्रेवाल और देहरादून के डीएफओ वैभव कुमार ने पूजा–अर्चना के बाद विधिवत शुभारंभ किया। निगम के अधिकारियों ने बताया कि पिछले खनन सत्र 2०25–26 में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, उपखनिज क्रेताओं, श्रमिकों और कर्मचारियों के सहयोग से जाखन–०1 लॉट से शत–प्रतिशत निकासी की गई। इस दौरान देहरादून जनपद से करीब 17 लाख टन उपखनिज निकाला गया, जिससे राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त हुआ। अधिकारियों ने कहा कि नए खनन सत्र में भी निकासी कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों और उपखनिज क्रेताओं का सहयोग जरूरी है।इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि के साथ स्थानीय लोगों को किफायती दरों पर उपखनिज उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी।प्रबंध निदेशक नीना ग्रेवाल ने निकासी कार्य को व्यवस्थित, पारदर्शी और निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित करने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए भी निगम से सहयोग मांगा। कार्यक्रम में डीएफओ वैभव कुमार, एसडीओ उदय गौड़, थानों वन रेंजर एलएन डोभाल, डीएलएम ऊषा पुरी सहित वन विकास निगम और वन विभाग के अधिकारी–कर्मचारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और उपखनिज क्रेता मौजूद रहे।

पहली बार हुआ दिव्यांग बच्चों का खेल महोत्सव

कोटद्वार(आरएनएस)। विकासखंड जयहरीखाल के ब्लॉक संसाधन केंद्र खुण्डोली में समग्र शिक्षा के अंतर्गत पहली बार ब्लॉक स्तरीय एकीकृत खेल महोत्सव आयोजित किया गया। ग्राम प्रधान ओडल रेखा देवी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और संचालन ब्लॉक समन्वयक चंद्रमोहन रावत ने किया। महोत्सव का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को समान अवसर प्रदान कर उनकी प्रतिभा और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करना रहा। इस दौरान बौद्धिक, शारीरिक, दृष्टि, श्रवण, ऑटिज्म और विकासात्मक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों ने उत्साह से हिस्सा लिया।महोत्सव में बोच्चे बॉल, सॉफ्ट बॉल, मेडिसिन थ्रो बॉल, व्हीलचेयर सिंगल, नींबू-चम्मच दौड़, म्यूजिकल चेयर, फन रेस और रस्साकशी जैसी प्रतियोगिताएं हुईं। प्रतियोगिता में जीआईसी सेंधीखाल की शीतल ने बोच्चे बॉल की लोकोमोटर श्रेणी और म्यूजिकल चेयर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं जीजीआईसी लैंसडौन के अभिनव कुक्रेती ने नींबू-चम्मच दौड़, रिले/फन रेस और सॉफ्ट बॉल/मेडिसिन थ्रो बॉल में प्रथम स्थान हासिल किया तथा रस्साकशी में भी टीम के साथ भाग लिया। राजीव गांधी आवासीय विद्यालय के बच्चों ने भी इसमें हिस्सा लिया। आयोजकों ने बताया कि ऐसे आयोजन बच्चों में अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करते हैं। इस दौरान विशेष शिक्षिकाएं प्रीति रावत व संगीता, व्यायाम शिक्षक प्रतीक्षित पंवार और प्रधानाध्यापक विक्रम सिंह रावत सहित कई शिक्षक मौजूद रहे।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

—प्रबंधक विज्ञापन

स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शोध को धरातल पर उतारना होगा

श्रीनगर गढ़वाल(आरएनएस)। राजकीय मेडिकल कॉलेज में उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड राज्य शाखा के 29वें आईएपीएसएम राष्ट्रीय सम्मेलन–2०26 का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। दो दिवसीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को मजबूत बनाने के उपायों पर मंथन करेंगे। कहा गया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शोध को धरातल पर उतारना होगा। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता, शोध, स्वच्छता और रोग नियंत्रण पर जोर दिया गया। चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि जलवायु

सर्वे के अनुरूप बाईपास निर्माण न होने पर आक्रोश

नई टिहरी(आरएनएस)। लंबगांव बाईपास का निर्माण कार्य सर्वे के अनुरूप न होने पर स्यालगी के ग्रामीणों में आक्रोश जताया। कहा कि कुछ ग्रामीणों ने बिना वजह के काम रोक दिया है। अपर जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में ग्रामीणों ने बंद पड़े कार्य को शुरू करवाने और जल्द उसे पूरा करने की गुहार लगाई। लंबगांव बाजार को जाम की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए 4.2 किलोमीटर लंबगांव–सरखोल–पिपलोगी–स्यालगी बाईपास का निर्माण कार्य किया जा रहा है। संदीप कलूड़ा, सुखदेव कलूड़ा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीणों ने एडीएम शैलेंद्र सिंह नेगी को इस संबंध में ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि प्रांतीय खंड लोनिवि बौराड़ी की ओर से लंबगांव बाईपास का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है लेकिन ठेकेदार ने बाईपास निर्माण कार्य हेड से न करके उल्टा पिपलोगी से शुरू करवाया गया है। बताया कि दोनों तरफ से करीब 4 किमी सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और मात्र 2०० मीटर का कार्य शेष रह गया है। कुछ ग्रामीणों ने बिना किसी वजह के कार्य को रुकवा दिया है। आरोप लगाया कि सड़क निर्माण की देखरेख कर रहे लोनिवि कर्मी भी ग्रामीणों को गुमराह करने में लगा है। जल्द निर्माण कार्य पूरा नहीं होता तो ग्रामीण आंदोलन शुरू करेंगे।

बदहाल सड़कों का जल्द निर्माण करवाएं:प्रेमचंद अग्रवाल

ऋषिकेश(आरएनएस)। विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने जल संस्थान एवं नगर निगम के अधिकारियों संग बैठक कर पेरी अर्बन योजना की समीक्षा की। उन्होंने पेयजल योजना के लिए खोली गई सड़कों का निर्माण नहीं होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को बदहाल सड़कों का जल्द निर्माण कराने के निर्देश दिए।

बैराज मार्ग स्थित कैंप कार्यालय में विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने जल संस्थान एवं नगर निगम के अधिकारियों संग बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से बापू ग्राम, शिवाजी नगर, मालवीय नगर, गीता नगर सहित अन्य क्षेत्रों में वर्ष 2०21 से 2०24 के बीच पेरी अर्बन पेयजल योजना के

परिवर्तन और जनस्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां वर्तमान समय के प्रमुख विषय हैं। इनसे निपटने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग और शोध आधारित स्वास्थ्य नीतियां विकसित करना जरूरी है। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के साथ उसकी गुणवत्ता और मरीजों को मिलने वाले उपचार पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉ. आशुतोष सयाना ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए शोध को धरातल पर उतारना, आधुनिक तकनीक का लाभ सभी तक पहुंचाना और स्वास्थ्य सेवाओं में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना जरूरी है।आईएपीएसएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अतुल कोतवाल ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने पर ध्यान देना

होगा। नई पीढ़ी के जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों और मेडिकल विद्यार्थियों को एआई के उपयोग, उसकी सीमाओं और संभावनाओं से परिचित कराना होगा ताकि वे इसका जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सकें। सम्मेलन में पौड़ी की सीएमओ डॉ. मेघना असवाल ने स्वास्थ्य मंत्री से जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती का अनुरोध किया। सम्मेलन में आईएपीएसएम के राष्ट्रीय सचिव डॉ. मनीष कुमार सिंह, स्टेट प्रेसिडेंट डॉ. हरिशंकर जोशी, स्टेट सेक्रेटरी डॉ. संदीप कुमार, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीएमएस रावत, आयोजन अध्यक्ष डॉ. जानकी बर्तवाल और सचिव डॉ. सुरेंद्र सिंह सहित विभिन्न राज्यों से आए विशेषज्ञ, फैकल्टी सदस्य और मेडिकल छात्र–छात्राएं मौजूद रहे।

टूटी सड़कों के विरोध में व्यापारी और सामाजिक संगठन सड़क पर उतरे

हरिद्वार(आरएनएस)। उत्तरी हरिद्वार की बदहाल सड़कों और गहरे गड्ढों के विरोध में व्यापारियों और सामाजिक संगठनों ने प्रदर्शन किया। महानगर व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुनील सेठी के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों की जल्द मरम्मत कराने की मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द सड़कें ठीक नहीं हुईं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। साथ ही सीवर कार्यदायी संस्था, लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। सुनील सेठी के नेतृत्व में जुटे व्यापारियों और क्षेत्रवासियों ने कहा कि सीवर कार्यदायी संस्था, लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई की लापरवाही से सड़कें बदहाल हैं।

आरोप है कि गड्ढों के कारण रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं।गुरुवार रात उत्तरी हरिद्वार में सीवर कार्यदायी संस्था की लापरवाही के चलते एक युवक के दुर्घटना में घायल होने का मामला भी सामने आया। सेठी ने जिलाधिकारी से जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की।उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर सड़कें इतनी खराब हैं कि पैदल चलने वालों से लेकर दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों तक को परेशानी उठानी पड़ रही है। स्कूल बसों के गड्ढों में धंसने का खतरा बना रहता है और वाहनों के टायर फटने व खराब होने की शिकायतें भी मिल रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी शिकायत भेजकर हरिद्वार की सड़कों की स्थिति का संज्ञान लेने की मांग की।

पहाड़ी महासभा के अध्यक्ष तरुण व्यास, महंत शुभम गिरी, गायत्री व्यापार मंडल अध्यक्ष भागीरथ प्रजापति और संगठन महामंत्री हरिमोहन भारद्वाज ने कहा कि बिना उचित योजना और सूचना के सड़कें खोदने से लोगों को बिजली–पानी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले से टूटी सड़कों की मरम्मत किए बिना बार–बार खुदाई किए जाने से परेशानी बढ़ रही है। उन्होंने संबंधित विभागों से काम में समन्वय रखने और खोदी गई सड़कों को तत्काल ठीक कराने की मांग की। प्रदर्शन में लालजी यादव, सतनाम सिंह, गोकुल डबराल, देवेंद्र गोयल, मेघराज, धर्मेन्द्र बब्बर, श्रीनिवास गोयल, सन्नी अरोड़ा, श्रेय शास्त्री, विकास गुप्ता, सावन कुमार, राजेश पांडे, सुशील कुमार, हरीश अरोड़ा, ओमप्रकाश भट्ट, गौरव खन्ना, पावन पांडे सहित व्यापारी और क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

बदहाल सड़कों का जल्द निर्माण करवाएं:प्रेमचंद अग्रवाल

तहत कराए गए कार्यों के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की अध्यतन जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के सुधार एवं पुनर्निर्माण के लिए जल संस्थान की ओर से नगर निगम को 13 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है, इसके बावजूद अब तक सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है।

सड़कों का निर्माण लंबित रहने पर विधायक ने नगर आयुक्त के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सड़कों की बदहाल स्थिति के कारण पिछले कई वर्षों से क्षेत्रीय जनता को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। आम नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही है, ऐसे में धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद निर्माण

कार्य में देरी होना गंभीर विषय है। उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सड़कों के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा।

कहा कि जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना अधिकारियों की जिम्मेदारी है और विकास कार्यों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।नगर आयुक्त विजय नाथ शुक्ला ने विधायक को आश्वासित किया कि संबंधित क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण जल्द ही करा लिया जाएगा। मौके पर जलकल अभियंता अरुण रावत, अधिशासी अभियंता आरके राणा आदि उपस्थित रहे।

कसरत करने के बाद इन 5 तरीकों से करें रिकवरी, जल्द मिलेगी राहत

कसरत करने के बाद शरीर को ठीक से आराम देना उतना ही जरूरी है, जितना कि व्यायाम करना। कसरत के बाद शरीर की मांसपेशियों और जोड़ों पर जोर पड़ता है, जिसके कारण उनमें दर्द और अकड़न जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इनसे राहत पाने के लिए शरीर को ठीक से आराम देना जरूरी है। आइए आज हम आपको कसरत के बाद शरीर की रिकवरी के लिए 5 आसान और प्रभावी तरीके बताते हैं।

पानी की कमी न होने दें : कसरत के बाद शरीर को पानी की कमी से बचना बहुत जरूरी है। जब आप कसरत करते हैं तो शरीर से बहुत पसीना निकलता है, जिससे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी पीने से शरीर को फिर से तरल पदार्थ मिलता है और यह तेजी से ठीक होता है। इसके अलावा आप नारियल पानी या फलों का रस भी पी सकते हैं। इससे शरीर को जरूरी खनिज लवण भी मिलते हैं, जो रिकवरी में मदद करते हैं।

प्रोटीन वाला खाना खाएं : कसरत के बाद प्रोटीन वाला खाना खाना बहुत फायदेमंद हो सकता है। प्रोटीन मांसपेशियों की मरम्मत करने और उन्हें मजबूत बनाने में मदद करती है। इसके लिए आप दाल, दूध, दही या चिकन जैसी चीजें खा सकते हैं। इसके अलावा आप प्रोटीन शेक या बार भी ले सकते हैं, जो जल्दी और आसानी से प्रोटीन प्रदान करते हैं। इससे आपकी मांसपेशियां तेजी से ठीक होती हैं और आप जल्दी से तैयार हो जाते हैं।

स्ट्रेचिंग करें : कसरत के बाद स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह मांसपेशियों को आराम देती है और खिंचाव कम करती है। इससे रक्त संचार भी बढ़ता है, जिससे शरीर में जमा लैक्टिक एसिड बाहर निकलता है और दर्द कम होता है। इसके अलावा स्ट्रेचिंग शरीर का लचीलापन बढ़ाती है, जिससे अगली बार की कसरत आसान हो जाती है। इससे शरीर में ताजगी और आराम महसूस होता है, जिससे आपकी रिकवरी प्रक्रिया भी बेहतर होती है।

पूरी नींद लें : पूरी नींद लेना शरीर की रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। जब आप सोते हैं तो आपका शरीर खुद ही मरम्मत करता रहता है और थकान दूर करता है। अच्छी नींद लेने से आपकी मांसपेशियां ठीक होती हैं और अगली बार की कसरत करने की ऊर्जा मिलती है। कोशिश करें कि आप रोजाना 7-8 घंटे की नींद लें ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके। इससे आप तरोताजा महसूस करेंगे और आपकी कसरत भी बेहतर होगी।

आराम करें : कभी-कभी आराम करना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। अगर आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है या दर्द हो रहा है तो एक दिन पूरी तरह आराम करें। इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें, बल्कि हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जैसे कि चलना या योग करना बेहतर रहेगा। इससे आपका शरीर जल्दी ठीक होगा और आप अगली बार की कसरत के लिए तैयार हो जाएंगे।

वजन उठाने वाली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जान लें ये 5 बातें

वजन उठाने वाली एक्सरसाइज को अक्सर लोग जिम में शरीर बनाने और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप इसका अभ्यास बिना किसी योजना के कर दें। दरअसल, वजन उठाने वाली एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। आइए आज हम आपको वजन उठाने वाली एक्सरसाइज से जुड़ी अहम बातें बताते हैं।

सबसे पहले डॉक्टर से लें सलाह : वजन उठाने वाली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। खासतौर से अगर आप पहले से कोई बीमारी या चोट से जूझ रहे हैं या आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा है। डॉक्टर आपकी सेहत का आकलन करके आपको वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करने की इजाजत दे सकते हैं या नहीं। इसके अलावा डॉक्टर आपको सही आहार और एक्सरसाइज के बारे में भी बता सकते हैं।

प्रशिक्षक से लें मार्गदर्शन : वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करते समय शरीर की मुद्रा का सही होना जरूरी है क्योंकि गलत तरीके से की गई एक्सरसाइज से चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप वजन उठाने वाली एक्सरसाइज शुरू करने से पहले किसी अच्छे प्रशिक्षक से मार्गदर्शन लें। इसके अलावा आप ऑनलाइन वीडियो देखकर भी वजन उठाने वाली एक्सरसाइज की सही तकनीक और फॉर्म को सीख सकते हैं।

धीरे-धीरे बढ़ाएं वजन : अगर आप वजन उठाने वाली एक्सरसाइज से जुड़ी सभी तकनीक और फॉर्म सीख भी जाते हैं तो भी आपको शुरूआत में हल्का वजन उठाना चाहिए। यह मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इससे आपको सही फॉर्म को बनाए रखने में मदद मिलेगी। साथ ही आपको अधिक वजन उठाने के कारण चोट लगने का खतरा भी नहीं रहेगा। इसके बाद ही आप धीरे-धीरे वजन बढ़ा सकते हैं।

वार्मअप करना है जरूरी : वजन उठाने वाली एक्सरसाइज से पहले वार्मअप करना बहुत जरूरी है। दरअसल, जब आप अपने शरीर को गर्म करते हैं तो इससे आपके दिल की धड़कनें बढ़ती हैं और आपकी मांसपेशियां सक्रिय हो जाती हैं। इससे आपके शरीर में लचीलापन भी आता है और आप आसानी से वजन उठाने वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा वार्मअप करने से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे शरीर में मौजूद जमी हुई चर्बी आसानी से पिघलने लगती है।

सेहत के बारे में बहुत कुछ बताती है आंखें

आंखें बाहरी दुनिया के दृश्यों को दिखाने के अलावा और सेहत के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। ये अपनी स्थितियों के जरिए हमारे समग्र स्वास्थ्य का हाल बता सकती हैं। आपकी आंखें मधुमेह से लेकर कोरोना वायरस जैसी महमारी तक विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं के शुरुआती चेतावनी संकेत दे सकती हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि आंखें किन-किन स्वास्थ्य जोखिमों की ओर इशारा करती हैं।

आंखों में खुजली : एक बार फिर से हर दिन कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है और यह बहुत परेशानी पैदा कर रहा है। इसके बुखार, थकान और खांसी जैसे सामान्य लक्षणों से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह महामारी आंखों में खुजली भी उत्पन्न करती है। नए कोविड वैरिएंट एक्सबीबी 1.16, जिसे आर्कटुरस के नाम से भी जाना जाता है, इसका मुख्य लक्षण भी आंखों में खुजली होना ही है।

धुंधली नजरें : धुंधली नजरें मधुमेह का संकेत दे सकती हैं। यह एक बीमारी है, जो रक्त में शर्करा के उच्च स्तर के कारण होती है। अनियंत्रित मधुमेह से डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, जिससे आंखों में छोटी रक्त वाहिकाएं रक्त और तरल पदार्थ का रिसाव करती हैं। इसके परिणामस्वरूप



धुंधली नजरें और रात में देखने में कठिनाई होती है। अगर आप मधुमेह को लेकर चिंतित हैं तो इन पांच योगासनों को आजमाकर उसे नियंत्रित करने में सफल हो सकते हैं।

कॉर्निया के चारों ओर गोला बनना : कॉर्नियल आर्कस एक ऐसी स्थिति है, जिसमें कॉर्निया के बाहरी किनारे पर वसा जमा होकर एक ग्रे-सफेद रेखा बनती है। कुछ मामलों में डिपॉजिट एक पूरा घेरा बना सकता है और आंखों का रंग भी बदल सकता है। हालांकि, यह स्थिति आमतौर पर वृद्ध व्यक्तियों में दिखती है। इसी तरह 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भी यह

पता होना चाहिए कि यह खतरनाक रूप से उच्च कोलेस्ट्रॉल (हृदय रोग) का संकेत हो सकता है।

उभरी हुई आंखें : उभरी हुई आंखें ग्रेव्स रोग का संकेत दे सकती हैं। यह एक ऐसी स्थिति जिसके परिणामस्वरूप थायराइड हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है। इसके अन्य लक्षणों में चीजें को दोहरा दिखाई देना, नजरें कमजोर होना, हाथ कांपना, वजन घटना और दस्त शामिल हैं। हालांकि, दवा और सर्जरी जैसे इलाज हार्मोन उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। आंखों की समस्या को हल्के में न लें क्योंकि ग्रेव्स घातक भी साबित हो सकता है।

झुकी हुई पलकें : झुकी हुई पलकें मायस्थेनिया ग्रेविस का संकेत दे सकती हैं। यह एक आटोइम्यून बीमारी है, जो शरीर की मांसपेशियों को कमजोर करती है। मायस्थेनिया ग्रेविस मुख्य रूप से आंख, चेहरे और गले की मांसपेशियों को प्रभावित करती है। इसके कारण बोलने, चबाने या कुछ भी निगलने में काफी मुश्किल होती है। इस बीमारी के लक्षणों को नियंत्रित करने के लिए कई दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ रोगियों को थाइमस ग्रंथि हटाने की सर्जरी की आवश्यकता भी हो सकती है।



शब्द सामर्थ्य -067

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. बात, घटना, माजरा, मुकदमा (उर्दू) 3. अलावा, अतिरिक्त 6. प्रेम, इच्छा 7. मां का बच्चे के प्रति प्रेम 8. गलती, जुर्म, गुनाह, दोष 10. मग्न, लीन, खुश, प्रसन्न 12. धनुष, समादेश, फौजी टुकड़ी 13. एक कल्पित पत्थर जो लोहे को छूकर सोना बना देता है 16. हिम्मत, साहस, सामर्थ्य 17. बनावटी,

अनुकृति, असली का विलोम 18. अबोध, नासमझ 20. ब्रह्मापुत्र एक प्रसिद्ध हरिभक्त देवर्षि 22. गहरा नीला, काला 23. व्याकुल, बेसब्र 24. मन, चित्त, आदरसूचक तथा सहमति सूचक एक शब्द।

ऊपर से नीचे

1. स्वामी, नाथ 2. बेबस, मजबूर, विवश 3. अन्याय, अत्याचार, जुल्म 4. मध्य एशिया का एक देश 5.

पुस्तक 9. बहादुर, वीर 11. सैनिक विद्रोह 12. नीच, अधम 12 ए. प्रणाम, झुकना 13. भरण-पोषण करना, परवरिश करना, छोटा झूला, हिंडोला 14. प्रमाण, प्रमाणिक कथन 15. स्वाभाविक ढंक, योग्यता, लियाकत, सभ्यता और शिष्टता, शऊर (उ.) 19. बिजली, तड़ित 21. रात में दिखाई न पड़ने का नेत्र संबंधी रोग।

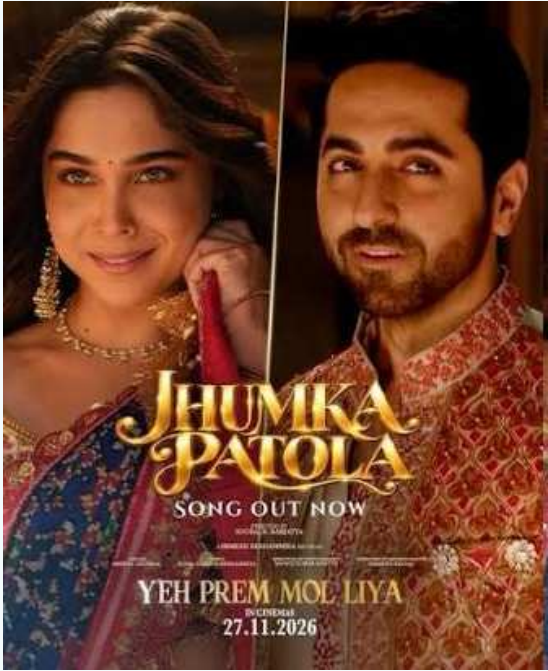
शब्द सामर्थ्य क्रमांक 66 का हल

प	सं	द		सिं	हा	स	न	
ख		म	ज	दू	र		का	म
वा	द	क		र		सं	ब	ल
इ		ल	ज्जा		म	स्का		य
	बा			बि	हा	र		
सु	धा	क	र		न			औ
रं		म		कि	ता	ब		स
ग		अ	र	सा		हु	ज्ज	त
	श	क्ल		न	मि	त		न

आयुष्मान खुराना की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का गाना झुमका पटोला जारी!

अभिनेता आयुष्मान खुराना और अभिनेत्री शरवरी की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' का तीसरा गाना 'झुमका पटोला' जारी कर दिया गया है। फिल्म के पिछले दो गानों 'ये प्रेम मोल लिया' और 'जय अम्बे बोल' के बाद इस नए गाने को भी श्रोताओं का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। हिमेश रेशमिया के संगीत और गायिका श्रेया घोषाल की सुरीली आवाज से सजे इस गाने में उत्सव और संगीत समारोह जैसा माहौल देखने को मिलता है।

'झुमका पटोला' का निर्माण हिमेश रेशमिया के संगीत संस्थान हिमेश रेशमिया मेलोडीज' के बैनर तले किया गया है। इसके बोल सोनिया कपूर रेशमिया ने लिखे हैं, जबकि मेघदीप बोस ने संगीत संयोजन और निर्माण की जिम्मेदारी संभाली है। गाने की धुन और गायकी इसे फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में शामिल कर रही हैं।



गाने के वीडियो में शरवरी और अभिनेत्री सौम्या टंडन नृत्य करती नजर आ रही हैं। रंगीन दृश्यों और उत्सवी अंदाज से सजे इस गीत में दोनों अभिनेत्रियों की प्रस्तुति देखने को मिलती है। फिल्म के पहले दो गानों के बाद 'झुमका पटोला' के जारी होने से इसके संगीत को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है।

सूरज बड़जात्या के राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये 'प्रेम मोल लिया' एक पारिवारिक नाट्य फिल्म है। इसमें आयुष्मान खुराना और शरवरी के साथ अनुपम खेर, सीमा पाहवा, सुप्रिया पाठक, स्वानंद किरकिरे और श्रुति सेठ सहित कई जाने-माने कलाकार नजर आएंगे।

फिल्म की कहानी और पारिवारिक परिवेश को लेकर दर्शकों के बीच उत्सुकता बनी हुई है। निर्माताओं को उम्मीद है कि फिल्म के गीत दर्शकों के बीच अपनी जगह बनाएंगे और इसकी लोकप्रियता बढ़ाने में मदद करेंगे।

'ये प्रेम मोल लिया' 27 नवंबर, 2026 को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के नए गाने के साथ अब दर्शकों की निगाहें इसकी रिलीज और पर्दे पर आयुष्मान खुराना व शरवरी की जोड़ी देखने पर टिकी हैं।

भगवा वस्त्रों में भक्ति भाव से नृत्य करते नजर आए अभिनेता अल्लारी नरेश

दक्षिण भारतीय अभिनेता अल्लारी नरेश की आगामी भक्ति प्रधान फिल्म 'कनक दुर्गा' का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। पोस्टर में अभिनेता भगवा वस्त्र पहने भक्ति भाव में डूबकर नृत्य करते दिखाई दे रहे हैं। उनका यह रूप आस्था, आध्यात्मिकता और देवी कनक दुर्गा की दिव्य उपस्थिति से प्रेरित कहानी की झलक पेश करता है।

फिल्म में अल्लारी नरेश के साथ काजल चौधरी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। इसका निर्देशन प्रदीप मद्दाली ने किया है, जबकि बीवीएस रवि ने कहानी लिखने के साथ इसके निर्माण की जिम्मेदारी भी संभाली है। बिड़ला स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत और टेम्पल टाउन पिक्चर्स के बैनर तले निर्मित इस फिल्म में भक्ति के साथ एक्शन, भावनात्मक घटनाक्रम और संगीत का मेल देखने को मिलेगा।

'कनक दुर्गा' में देवी के प्रति श्रद्धा और आध्यात्मिक आस्था को केंद्र में रखा गया है। फिल्म निर्माताओं का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को मनोरंजक कहानी, प्रभावशाली दृश्यों और संगीत के माध्यम से बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाना है। पहले पोस्टर में अल्लारी नरेश का भक्तिपूर्ण अंदाज फिल्म की विषयवस्तु की ओर संकेत करता है।

फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी प्रसिद्ध संगीतकार थमन एस को सौंपी गई है। निर्माताओं ने इसे अखिल भारतीय स्तर पर प्रदर्शित करने की योजना बनाई है, ताकि विभिन्न भाषाओं के दर्शक भी इस कहानी से जुड़ सकें।

फिलहाल 'कनक दुर्गा' का निर्माण कार्य जारी है। निर्माताओं के अनुसार, फिल्म को पहले दुनियाभर के सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया जाएगा। इसके बाद यह विशेष रूप से जी5 तेलुगु पर प्रसारण के लिए उपलब्ध होगी।

फिल्म निर्माताओं ने यह भी जानकारी दी है कि इसका पहला गीत जल्द जारी किया जाएगा। अब दर्शकों को फिल्म के संगीत, अन्य कलाकारों, प्रदर्शन की तारीख और आगे जारी होने वाली झलकियों का इंतजार है। अल्लारी नरेश को भक्ति प्रधान भूमिका में देखने के लिए उनके प्रशंसकों में उत्सुकता बनी हुई है।

बिना पहचान वाले ट्रोलर्स की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देती मृणाल ठाकुर

अभिनेत्री मृणाल ठाकुर ने सामाजिक माध्यमों पर बिना पहचान उजागर किए नफरत और नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों को स्पष्ट जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वह आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से स्वीकार करती हैं, लेकिन ऐसे लोगों की नकारात्मक टिप्पणियों को महत्व नहीं देतीं, जिनकी अपनी कोई पहचान तक सामने नहीं होती और जिनकी प्रोफाइल तस्वीर भी नहीं लगी होती। मृणाल का मानना है कि किसी फिल्म की सफलता का आकलन केवल सिनेमाघरों में होने वाली कमाई के आधार पर नहीं किया जा सकता। डिजिटल मंचों के बढ़ते प्रभाव ने फिल्मों की सफलता को देखने का नजरिया बदल दिया है।

नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के बारे में पूछे जाने पर मृणाल ने कहा कि वह हमेशा आलोचनाओं को सकारात्मक रूप से लेने में विश्वास करती हैं। हालांकि, वह उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहतीं, जिनकी सामाजिक माध्यमों पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर तक नहीं होती। उनके मुताबिक, अपनी पहचान छिपाकर दूसरों को नीचा दिखाते वाले लोगों की टिप्पणियां उनके लिए कोई मायने नहीं रखतीं।

इस साल कुछ फिल्मों के सिनेमाघरों में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाने के बावजूद मृणाल का मानना है कि उनकी सफलता का फैसला केवल बॉक्स ऑफिस की कमाई से नहीं होना चाहिए। अपनी हालिया फिल्म 'पूजा मेरी जान' को डिजिटल मंच पर मिल रही सराहना के बीच उन्होंने कहा कि आज के दौर में फिल्म किस माध्यम



से दर्शकों तक पहुंचती है, इससे अधिक महत्वपूर्ण उसकी कहानी, विषय, किरदार और निर्देशक का नजरिया है।

मृणाल ने फिल्म 'लापता लेडीज' का उदाहरण देते हुए बताया कि कई बार सिनेमाघरों में दर्शकों का पर्याप्त ध्यान नहीं खींच पाने वाली फिल्मों को डिजिटल मंच पर रिलीज होने के बाद व्यापक सराहना मिलती है। उन्होंने कहा कि 'लापता लेडीज' को सिनेमाघरों में अपेक्षित ध्यान नहीं मिला, लेकिन डिजिटल मंच पर आने के बाद दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया। इससे पता चलता है कि किसी फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने और अपनी पहचान बनाने में समय लग सकता है।

मृणाल ने अपनी फिल्म 'डकैत' को मिली प्रतिक्रियाओं का जिक्र करते हुए बताया कि कई प्रशंसकों ने उनसे कहा कि उन्हें सिनेमाघरों में यह फिल्म नहीं देखने का अफसोस है। कुछ लोगों ने इसके लिए उनसे माफी तक मांगी। अभिनेत्री के मुताबिक, दर्शकों की ऐसी प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि फिल्मों को लेकर लोगों की पसंद और देखने का तरीका लगातार बदल रहा है।

उन्होंने माना कि बदलते समय के साथ फिल्मों के प्रचार और विपणन के तरीके भी बदल गए हैं। दर्शकों की पसंद को समझना और उनके साथ जुड़ने के नए तरीकों को सीखना जरूरी हो गया है।

30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर आएगी कीर्ति सुरेश की पहली वेब श्रृंखला अक्का



राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश अब डिजिटल मनोरंजन की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। उनकी पहली वेब श्रृंखला 'अक्का' में अभिनेत्री राधिका आटे भी प्रमुख भूमिका में नजर आएंगी। यह एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित अपराध-रोमांचक श्रृंखला है, जिसकी कहानी 1980 के दशक के दक्षिण भारत में बसे एक काल्पनिक शहर पेनुरु के इर्द-गिर्द घूमती है। यहां अपराध जगत पर

ताकतवर महिलाओं का वर्चस्व है। खबरों के मुताबिक, इस श्रृंखला का प्रीमियर 30 अक्टूबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर होगा।

'अक्का' की कहानी गैंगस्टर रानियों के एक शक्तिशाली समूह पर केंद्रित है, जिन्होंने शहर के अपराध जगत में अपना साम्राज्य स्थापित कर रखा है। लेकिन एक बाहरी व्यक्ति के आने से उनके वर्चस्व पर खतरा मंडराने लगता है। इसके बाद धोखेबाजी, बदले, सत्ता संघर्ष और अस्तित्व की लड़ाई

का सिलसिला शुरू होता है।

इस श्रृंखला का लेखन और निर्देशन धर्मराज शेटी ने किया है। यह उनके निर्देशन की पहली परियोजना है। कीर्ति सुरेश और राधिका आटे मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि तन्वी आजमी और अंशुमान पुष्कर भी महत्वपूर्ण किरदार निभाते दिखाई देंगे।

कीर्ति सुरेश के लिए यह परियोजना खास है, क्योंकि इसके माध्यम से वह पहली बार किसी प्रमुख डिजिटल प्रसारण मंच पर अपनी शुरुआत करेंगी। वहीं, कीर्ति और राधिका पहली बार एक साथ अभिनय करती नजर आएंगी। दोनों अभिनेत्रियों के प्रशंसकों को इस नई जोड़ी से काफी उम्मीदें हैं।

'अक्का' की घोषणा नवंबर 2023 में की गई थी। इसके बाद से इस परियोजना पर काम चल रहा है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 'बॉलीवुड हंगामा' ने श्रृंखला के 30 अक्टूबर 2026 को प्रसारित होने की जानकारी दी है। हालांकि, इसकी रिलीज से जुड़ी अंतिम जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणा को ही निर्णायक माना जाएगा।

इस श्रृंखला का निर्माण वाईआरएफ एंटरटेनमेंट ने किया है। कहानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले अपराध साम्राज्य, सत्ता की खींचतान, हिंसा, बदले और वर्चस्व की लड़ाई को प्रमुखता दी गई है।

एसआईआर रद्द करने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की मांग

रुद्रपुर(आरएनएस)। एसआईआर को रद्द करने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने और मतदाता सूची से हटाए गए नागरिकों के मताधिकार बहाल करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। किसानों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर गौरव पांडे को सौंपकर चुनाव सुधार लागू करने और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के दमन पर रोक लगाने की मांग की। किसानों ने ज्ञापन में आरोप लगाया कि एसआईआर के तहत पारदर्शिता के बिना बड़ी संख्या में नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे 13.41 करोड़ नागरिकों के मतदान के अधिकार प्रभावित हुए हैं। मोर्चा ने एसआईआर प्रक्रिया तत्काल रद्द करने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने तथा नागरिकों के मताधिकार बहाल करने की मांग की। प्रदर्शन में भूमि बचाओ मुहिम के अध्यक्ष जगतार सिंह बाजवा, भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह जीतू, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां के अध्यक्ष बल्ली सिंह चीमा, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष हरजिंदर संधू, अखिल भारतीय किसान सभा लोकमत के संयोजक जगीर सिंह, अखिल भारतीय किसान महासभा के संयोजक ललित मटियाली, सत्यपाल, धारा दिलेर रंधावा, खेम सिंह, राज किशोर, जसवीर सिंह, हीरा सिंह, सतनाम सिंह, कुलदीप सिंह, गुरजीत कोटिया और हरपाल सिंह चीमा रहे।

सड़क सुरक्षा में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई: डीएम

बागेश्वर(आरएनएस)। जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने जिला सभागार में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक ली। उन्होंने दुर्घटना संभावित स्थलों और ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर वहां सुधारात्मक कार्य प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क सुरक्षा में लापरवाही न बरतने की हिदायत दी। डीएम ने संबंधित विभागों को दुर्घटना संभावित स्थलों की फोटोग्राफ सहित अद्यतन सूची तैयार करने और वहां किए गए व प्रस्तावित कार्यों का ब्योरा देने को कहा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को शिकायत वाले मार्गों का निरीक्षण कर गड्ढों की मरम्मत गुणवत्ता के साथ कराने के निर्देश दिए। सानीउडियार क्षेत्र में सड़क के गड्ढों की शिकायतों का परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने को भी कहा। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट का प्रयोग सुनिश्चित करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान करने के निर्देश दिए। ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में चालान की संख्या कम मिलने पर नाराजगी जताते हुए नियमित जांच अभियान चलाने को कहा। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक अजय शाह, एसीएमओ अनुपमा ह्यांकी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

सू- दोकू क्र.067								
	2			6			1	
3				4			2	
							6	
6						4		
	9			5			6	1
4		3				9		2
	8		2				7	
1		2		4		9		6
नियम			सू-दोकू क्र.66 का हल					
1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गों का एक खंड बनता है। 2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है। 3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।			8	7	6	9	5	1
			1	3	9	2	8	4
			4	5	2	3	7	6
			2	8	5	4	6	7
			3	1	7	8	9	2
			6	9	4	1	3	5
			9	4	1	6	2	8
			7	2	8	5	1	3
			5	6	3	7	4	9

दीपावली और विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस अलर्ट!

अल्मोड़ा(आरएनएस)। पुलिस लाइन सभागार में एसएसपी चंद्रशेखर घोडके की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी और पुलिस कर्मचारी सम्मेलन आयोजित किया गया। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र और दीपावली पर्व के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने, अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की गई।

एसएसपी ने पुलिस अधिकारियों को बाजारों में पुलिस की दृश्यता बढ़ाने और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित गश्त तथा पिकेट ड्यूटी लगाने के निर्देश दिए। आगामी विधानसभा सत्र को देखते हुए जनपद में सघन जांच और सत्यापन अभियान चलाने, संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने तथा होटल और रेस्तरां की नियमित जांच करने को कहा गया। दीपावली पर पटाखा बाजारों, संवेदनशील क्षेत्रों और

चकराता में एक नवंबर को होगा खंड स्तरीय युवा महोत्सव

विकासनगर(आरएनएस)। युवाओं की प्रतिभा को मंच देने और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चकराता विकासखंड में एक नवंबर को खंड स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम खंड विकास अधिकारी कार्यालय ग्वासा पुल में होगा।

महोत्सव में सामूहिक एवं एकल लोक नृत्य, लोकगीत, कविता लेखन, चित्रकला, भाषण और नुक्कड़ नाटक समेत आठ विधाओं में प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के वही युवा प्रतिभाग कर सकेंगे, जो चकराता विकासखंड के मूल निवासी हैं। लोकगीत और लोक नृत्य में पारंपरिक संस्कृति को प्राथमिकता दी जाएगी।

फिल्मी गीतों और रिकॉर्डेड संगीत पर प्रतिबंध रहेगा।

विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाएगा। विजेताओं को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भी प्रतिभाग करने का अवसर मिलेगा। खंड विकास अधिकारी राकेश बिष्ट ने विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और युवक एवं महिला मंगल दलों से अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है। प्रतिभागियों के यात्रा, भोजन और आवास का खर्च विभाग की ओर से वहन किया जाएगा।

जिला अस्पताल के पास ही एएनएम प्रशिक्षण सेंटर चलाने की मांग

पिथौरागढ़(आरएनएस)। एएनएम प्रशिक्षण सेंटर की छात्राओं ने प्रशासन से जिला अस्पताल के समीप सुरक्षित और सुविधायुक्त माहौल में पढ़ाई की मांग की है। प्रशिक्षणार्थी छात्राओं का कहना है कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित और जानलेवा खतरों से भरे बडालू प्रशिक्षण केंद्र के भवन में जाना उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। सुरक्षा, पेयजल और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की अनदेखी से आक्रोशित छात्राएं जल्द ही डीएम से मुलाकात कर उन्हें अपना मांग पत्र सौंपेंगी। प्रशिक्षणार्थी छात्राओं ने कहा कि बीते

भीड़भाड़ वाले स्थानों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए। अल्मोड़ा और रानीखेत के अग्निशमन केंद्रों को भी सतर्क रहने और पटाखा बाजारों तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अग्निशमन वाहन व आवश्यक उपकरण तैयार रखने को कहा गया। एसएसपी ने स्मैक, गांजा और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने, शराब तस्करी और अवैध भांग की खेती के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मादक पदार्थों से जुड़े मामलों में आर्थिक और वित्तीय पहलुओं की गहन जांच कर अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने तथा गैंगस्टर अधिनियम के तहत प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए। बैठक में लंबित विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करने को कहा गया। महिला और नाबालिगों के विरुद्ध

सरकारी स्कूलों में कमजोर बच्चों की पढ़ाई सुधारने पर जोर

विकासनगर(आरएनएस)। सरकारी स्कूलों में कमजोर दक्षताओं वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई सुधारने के लिए जिले के 252 विद्यालयों में सुधारात्मक कार्ययोजना लागू करने पर जोर दिया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की ओर से जारी पत्र में विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कमियों की पहचान कर उनके अनुरूप शिक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। बीते पांच अक्तूबर को कक्षा दो, पांच और आठ के विद्यार्थियों के दक्षता आधारित आकलन के परिणामों के आधार पर विद्यालयों को तीन श्रेणियों में रखा गया है। इनमें 7० विद्यालय तत्काल फॉलोअप, 165 विद्यालय प्रदर्शन में गिरावट अथवा उच्च से मध्यम या निम्न स्तर पर पहुंचने और 17 विद्यालय अब भी निम्न स्तर पर होने के कारण विशेष निगरानी के दायरे में हैं। कार्ययोजना के तहत शिक्षकों को कमजोर दक्षताओं वाले बच्चों की पहचान कर अतिरिक्त अभ्यास कराने, समान कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह बनाने और उनकी प्रगति का नियमित आकलन करने को कहा गया है। नियमित शिक्षण में सुधारात्मक गतिविधियां शामिल करने के साथ स्थानीय परिवेश और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री का उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई में सुधार के लिए अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें घर पर पढ़ाई में सहयोग के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया गया है। डायट के प्राचार्य गोविंद राम जायसवाल ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को कार्ययोजना लागू कराने, विद्यालयों की नियमित निगरानी करने और की गई कार्रवाई की जानकारी उच्चाधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए हैं।

डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था मजबूत करें

बागेश्वर(आरएनएस)। जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने जिला गंगा समिति की मासिक बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नगर निकायों को डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था प्रभावी बनाने और स्वच्छता शुल्क की वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए।डीएम ने सड़क किनारे रखे कूड़ेदानों की नियमित निगरानी, समय पर कूड़ा उठान और वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को ट्रेनिंग ग्रांडंड के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया तेज करने तथा घरों से कूड़ा संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और अंतिम निस्तारण तक की पूरी प्रक्रिया का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए।उन्होंने विकासखंडों में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन संबंधी कार्यों का नियमित दस्तावेजीकरण करने को भी कहा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी एनएस नबियाल, जिला विकास अधिकारी संगीता आर्या और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विनोद जीना सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

जिला अस्पताल के पास ही एएनएम प्रशिक्षण सेंटर चलाने की मांग

सितंबर माह के शुरूआती दिनों भूस्खलन होने के कारण बडालू स्थित एएनएम सेंटर का संचालन जिला मुख्यालय से किया जा रहा है।जिसे अब वापस बडालू स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है। छात्राओं का कहना है कि वर्तमान में भवन जर्जर स्थिति में है। बारिश के दिनों में छतों से पानी टपकता है। पीने के पानी की भारी क्लिष्ट है। कहा कि सबसे गंभीर चिंता सुरक्षा को लेकर है, क्षेत्र में आए दिन जहरीले सांप निकलते रहते हैं। हाल ही में सांप के काटने से एक कुत्ते की तड़पकर हुई मौत ने छात्राओं में दहशत भर दी है। छात्राओं

अपराधों तथा साइबर ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई कर पीड़ितों को राहत दिलाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यक्तिगत तथा विभागीय समस्याएं भी सुनी गईं। एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। एसएसपी ने सितंबर में प्रभावी पुलिसिंग, मानवीय कार्यों और सराहनीय योगदान के लिए भिक्रियासैण चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक संजय जोशी सहित कुल 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बैठक में सीओ अल्मोड़ा बलवंत सिंह रावत, सीओ संचार राजीव कुमार टप्टा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी नरेंद्र सिंह कुंवर सहित विभिन्न थानों, शाखाओं और पुलिस इकाइयों के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।

सरकारी स्कूलों में कमजोर बच्चों की पढ़ाई सुधारने पर जोर

विकासनगर(आरएनएस)। सरकारी स्कूलों में कमजोर दक्षताओं वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई सुधारने के लिए जिले के 252 विद्यालयों में सुधारात्मक कार्ययोजना लागू करने पर जोर दिया गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की ओर से जारी पत्र में विद्यार्थियों की सीखने संबंधी कमियों की पहचान कर उनके अनुरूप शिक्षण कराने के निर्देश दिए गए हैं। बीते पांच अक्तूबर को कक्षा दो, पांच और आठ के विद्यार्थियों के दक्षता आधारित आकलन के परिणामों के आधार पर विद्यालयों को तीन श्रेणियों में रखा गया है। इनमें 7० विद्यालय तत्काल फॉलोअप, 165 विद्यालय प्रदर्शन में गिरावट अथवा उच्च से मध्यम या निम्न स्तर पर पहुंचने और 17 विद्यालय अब भी निम्न स्तर पर होने के कारण विशेष निगरानी के दायरे में हैं। कार्ययोजना के तहत शिक्षकों को कमजोर दक्षताओं वाले बच्चों की पहचान कर अतिरिक्त अभ्यास कराने, समान कठिनाइयों वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह बनाने और उनकी प्रगति का नियमित आकलन करने को कहा गया है। नियमित शिक्षण में सुधारात्मक गतिविधियां शामिल करने के साथ स्थानीय परिवेश और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री का उपयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बच्चों की पढ़ाई में सुधार के लिए अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें घर पर पढ़ाई में सहयोग के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया गया है। डायट के प्राचार्य गोविंद राम जायसवाल ने बताया कि संबंधित अधिकारियों को कार्ययोजना लागू कराने, विद्यालयों की नियमित निगरानी करने और की गई कार्रवाई की जानकारी उच्चाधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए हैं।

डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था मजबूत करें

बागेश्वर(आरएनएस)। जिलाधिकारी अपूर्वा पांडे ने जिला गंगा समिति की मासिक बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नगर निकायों को डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण व्यवस्था प्रभावी बनाने और स्वच्छता शुल्क की वसूली बढ़ाने के निर्देश दिए।डीएम ने सड़क किनारे रखे कूड़ेदानों की नियमित निगरानी, समय पर कूड़ा उठान और वैज्ञानिक निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को ट्रेनिंग ग्रांडंड के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया तेज करने तथा घरों से कूड़ा संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और अंतिम निस्तारण तक की पूरी प्रक्रिया का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए।उन्होंने विकासखंडों में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन संबंधी कार्यों का नियमित दस्तावेजीकरण करने को भी कहा। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी नरेश कुमार, अपर जिलाधिकारी एनएस नबियाल, जिला विकास अधिकारी संगीता आर्या और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी विनोद जीना सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

जिला अस्पताल के पास ही एएनएम प्रशिक्षण सेंटर चलाने की मांग

सितंबर माह के शुरूआती दिनों भूस्खलन होने के कारण बडालू स्थित एएनएम सेंटर का संचालन जिला मुख्यालय से किया जा रहा है।जिसे अब वापस बडालू स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है। छात्राओं का कहना है कि वर्तमान में भवन जर्जर स्थिति में है। बारिश के दिनों में छतों से पानी टपकता है। पीने के पानी की भारी क्लिष्ट है। कहा कि सबसे गंभीर चिंता सुरक्षा को लेकर है, क्षेत्र में आए दिन जहरीले सांप निकलते रहते हैं। हाल ही में सांप के काटने से एक कुत्ते की तड़पकर हुई मौत ने छात्राओं में दहशत भर दी है। छात्राओं

का कहना है कि एएनएम कोर्स के दौरान उन्हें 6 महीने तक जिला अस्पताल में रहकर व्यावहारिक प्रशिक्षण (नाइट व डे ड्यूटी) पूरा करना होता है। बडालू मुख्य बाजार और अस्पताल से काफी दूर है। ऐसे में हर रोज आने-जाने में समय और सुरक्षा का जोखिम तो रहता ही, साथ ही किसी छात्रा के अचानक बीमार पड़ने पर वक्त पर इलाज मिलना भी नामुमकिन हो जाएगा। उनका कहना है कि वे किसी व्यवस्था या फैसले का अकारण विरोध नहीं कर रही हैं, बल्कि अपनी बुनियादी सुरक्षा और सही प्रशिक्षण वातावरण की मांग कर रही हैं।

मंत्री ने माफी मांगकर संभाली किरकिरी

कार्यालय संवाददाता
देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में मंत्री सुबोध उनियाल का एक बयान अब उनके लिए असहज स्थिति पैदा करता नजर आ रहा है। गायक दलेर मेहंदी पर नशे से जुड़ी टिप्पणी के बाद मंत्री को माफी मांगनी पड़ी। मंत्री का पद केवल सत्ता और अधिकार का प्रतीक नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भी तकाजा करता है। ऐसे में किसी चर्चित कलाकार पर नशे को लेकर टिप्पणी करना और फिर माफी मांगने की स्थिति में पहुंच जाना कई सवाल खड़े करता है। यदि टिप्पणी तथ्यों पर आधारित थी, तो माफी की जरूरत क्यों पड़ी? और यदि बिना पर्याप्त आधार के बात कही गई, तो क्या यह सार्वजनिक पद की गरिमा के अनुरूप आचरण था?

सुबोध उनियाल की माफी को विवाद शांत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन इससे बयान के औचित्य पर उठे सवाल अपने आप खत्म नहीं हो जाते। सार्वजनिक मंच पर बोले गए शब्द वापस लेना आसान नहीं होता। खासकर तब, जब टिप्पणी किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से जुड़ी हो। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा होती है कि वह बोलने से पहले सोचें, तथ्यों को परखें और अपनी भाषा की मर्यादा बनाए रखें।

इस प्रकरण ने मंत्री की राजनीतिक सूझबूझ और सार्वजनिक संवाद के तौर-तरीकों पर भी बहस का अवसर दिया है। राजनीतिक विरोधियों को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिलना स्वाभाविक है, लेकिन असली सवाल दलगत राजनीति से बड़ा है कि क्या जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों के लिए भी सार्वजनिक बयानबाजी में जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए?

उत्तराखंड में नशा युवाओं और परिवारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार को ठोस कार्रवाई, जागरूकता और प्रभावी रोकथाम पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे मुद्दे को व्यक्तिगत टिप्पणियों और विवादों में उलझाने से समस्या का समाधान नहीं निकलता। जरूरत नशे के खिलाफ स्पष्ट नीति और जमीन पर परिणाम दिखाने की है, न कि ऐसी बयानबाजी की जो खुद विवाद का कारण बन जाए।

सुबोध उनियाल का यह प्रकरण सत्ता पक्ष के लिए भी एक संदेश है कि राजनीतिक हैसियत किसी बयान को सवालों से परे नहीं कर देती। माफी मांगना विवाद को थामने का रास्ता हो सकता है, लेकिन जवाबदेही से बचने का विकल्प नहीं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि मंत्री ने माफी क्यों मांगी, सवाल यह भी है कि ऐसी टिप्पणी करने से पहले उन्होंने तथ्यों और अपने पद की गरिमा का ध्यान क्यों नहीं रखा?

खरगे की टिप्पणी से तूफान..

◀ पृष्ठ 2 का शेष

प्रधानमंत्री और सरकार की आलोचना लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है। विपक्ष का दायित्व है कि वह सत्ता से सवाल पूछे, जबकि सत्तारूढ़ दल को आलोचना का जवाब तथ्यों और तर्कों से देना चाहिए। व्यक्तिगत टिप्पणियां इस बहस को मूल मुद्दों से भटका सकती हैं।

खरगे की टिप्पणी ने भाजपा को कांग्रेस की राजनीतिक शैली पर सवाल उठाने का अवसर दे दिया है। देशव्यापी विरोध के जरिए पार्टी इस विवाद को जनचर्चा में बनाए रखने की कोशिश करेगी। दूसरी ओर, कांग्रेस के सामने चुनौती है कि वह अपने अध्यक्ष के बयान पर उठे सवालों का जवाब देते हुए राजनीतिक मुद्दों पर अपनी पकड़ बनाए रखे। फिलहाल, खरगे की एक टिप्पणी ने भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव को नया मोड़ दे दिया है। भाजपा इसे राजनीतिक मर्यादा के उल्लंघन का मुद्दा बना रही है, जबकि कांग्रेस बयान के संदर्भ और उसके राजनीतिक अर्थ पर जोर दे रही है। इस विवाद का असर कितना व्यापक होगा, यह आने वाले दिनों में दोनों दलों की रणनीति और जनता की प्रतिक्रिया से तय होगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि राजनीतिक बहस में भाषा और आचरण भी अब दोनों दलों के लिए बड़ी परीक्षा बन गए हैं।

न्याय यात्रा के नाम पर राजनीतिक...

◀ पृष्ठ 2 का शेष

खाका भी होना चाहिए।

उत्तराखंड की राजनीति में न्याय यात्रा को लेकर जारी विवाद का असली केंद्र यही है। कांग्रेस इसे जनता की आवाज बनाने का दावा कर रही है, जबकि भाजपा इसे चुनाव से पहले राजनीतिक जमीन तैयार करने की कोशिश बता रही है। दोनों दलों के लिए यह आंदोलन अपनी-अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता साबित करने का अवसर भी है और चुनौती भी। 2027 के चुनाव में जनता यह भी देखेगी कि कौन-सा दल उसके सवालों को चुनावी मंच तक सीमित रखता है और कौन उन्हें समाधान तक पहुंचाने का प्रयास करता है। कांग्रेस की न्याय यात्रा की असली परीक्षा उसके उठाए मुद्दों की गंभीरता और निरंतरता में होगी, जबकि भाजपा की परीक्षा इन मुद्दों पर दिए जाने वाले जवाबों और सरकार के कामकाज से होगी।

फिलहाल, न्याय यात्रा के बहाने उत्तराखंड में सियासी घमासान तेज है। भाजपा इसे कांग्रेस का राजनीतिक ढोंग बता रही है और कांग्रेस इसे जनता के न्याय की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। लेकिन इस शोर के बीच सबसे अहम सवाल यही है कि राजनीतिक दलों की लड़ाई से आम जनता को क्या हासिल होगा? चुनावी आरोप-प्रत्यारोप के बीच यदि जनता के वास्तविक सवाल पीछे छूट गए, तो न्याय यात्रा हो या उसका विरोध दोनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे।

जौनसारियों को जनजाति प्रमाणपत्र देने पर लगे रोक: एडवोकेट विकेश

जौनसारी शब्द संशोधन के प्रस्ताव पर केंद्र के फैसले तक नए प्रमाणपत्र जारी न करने की मांग

संवाददाता
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जौनसारी के स्थान पर जौनसारी शब्द संशोधित कराने के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति करने का फैसला किया गया है। इस फैसले के बाद इस मुद्दे का प्रमुखता से उठाने वाले आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और देहरादून जिला प्रशासन से मांग की है कि जब तक इस मामले में केंद्र से फैसला नहीं होता तब तक जौनसार के किसी भी अगड़ी जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र जारी न किया जाए। विकेश सिंह नेगी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के गलत फैसले से हजारों अपात्र लोगों ने अनुसूचित जनजाति आरक्षण का लाभ लिया है और वहीं जौनसार का वंचित समाज जिनको इसका लाभ मिलना चाहिए था आज भी विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर है।

आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट

स्मैक व नगदी सहित एक गिरफ्तार

हमारे संवाददाता
देहरादून। नशा तस्करी में लिप्त एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसके पास से स्मैक व हजारों की नगदी बरामद की गयी है। जानकारी के अनुसार बीती शाम चैकिंग के दौरान विकासनगर पुलिस द्वारा बन्दरोवाला बाग बारुद फैक्ट्री रोड देहरादून पोंटा हाईवे के पास कुल्हाल, विकासनगर से एक आरोपी सन्वर उर्फ सोनू पुत्र अख्तर निवासी ग्राम कुन्जा ग्रान्ट पो0 ढालीपुर कोतवाली विकासनगर जिला देहरादून उम्र 32 वर्ष को 8.62 ग्राम स्मैक एवं स्मैक बेचकर अर्जित धनराशि 5300 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध कोतवाली विकासनगर में मु0अ0सं0-327/2026 धारा-8/21/27(1) एन0डी0पी0एस0 एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया।



विकेश नेगी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इस मामले में जों संस्तुति करने का फैसला लिया है, उससे स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार मानती है कि जौनसार में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मामले में गलती हो रही है। कोल्टा और बाजगी समुदाय के हकों पर जौनसार के अपात्र ब्राह्मण और क्षत्रिय आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और वहां के कोल्टा और बाजगी जातियों के लोग आज भी अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं। प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद स्थिति साफ हो गयी है

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर किया नमन

हमारे संवाददाता
देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज नेशविला रोड स्थित पथरिया पीर वाल्मीकि मंदिर में आदिकवि एवं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धापूर्वक माल्यार्पण कर नमन किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से सत्य, करुणा समानता और मानवता के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाया। उनके महान विचार और शिक्षाएं आज भी समाज को सदाचार, सामाजिक समरसता और लोककल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का जीवन और उनके आदर्श हमें समाज में प्रेम, सद्भाव और समानता की भावना को मजबूत करने का संदेश देते हैं। उनके विचारों को आत्मसात कर एक समरस एवं सशक्त समाज के निर्माण में योगदान देना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत, डॉ बबीता सहोत्रा, भावना चौधरी, सतेंद्र नाथ सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।



अभिनेत्री उर्मिला सनावर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

संवाददाता
देहरादून। हरिद्वार में पांच करोड़ रुपये की कथित रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अभिनेत्री उर्मिला सनावर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार अभिनेत्री को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, अभिनेत्री उर्मिला सनावर द्वारा रविदास धाम से जुड़ी संपत्ति अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि संपत्ति से जुड़े इस विवाद के दौरान पांच करोड़ रुपये की मांग भी की गई। पूर्व विधायक की बेटी ने अपनी शिकायत में



जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया था। शिकायत मिलने के बाद रानीपुर कोतवाली पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।

पुलिस ने अभिनेत्री उर्मिला सनावर को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी के दौरान कथित घटना में इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल

कि जौनसार में 28 नवम्बर 2000 के बाद जितने भी अनुसूचित जनजाति के प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं, वो पूरी तरह से अवैध हैं।

एडवोकेट विकेश नेगी ने कहा कि जिला प्रशासन को तत्काल प्रभाव से जौनसार के ब्राह्मण, खस और क्षत्रियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाणपत्र निरस्त कर देना चाहिए। इसके साथ ही जब तक केन्द्र सरकार इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लेता है तब तक राज्य के जौनसार क्षेत्र में कोई नया प्रमाणपत्र निर्गत नहीं किया जाना चाहिए।

एडवोकेट विकेश नेगी ने कहा कि 1967 में राष्ट्रपति के अध्यादेश और लोकुर-डेबुर कमेटी की रिपोर्ट में भी स्पष्ट कहा गया है कि जौनसार में क्षेत्र विशेष नहीं बल्कि समुदाय के आधार पर जनजाति का आरक्षण दिया गया है। इसमें साफ कहा गया है कि जौनसार के ब्राह्मणों, क्षत्रियों और खस को अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर किया नमन

हमारे संवाददाता
देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज नेशविला रोड स्थित पथरिया पीर वाल्मीकि मंदिर में आदिकवि एवं रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर श्रद्धापूर्वक माल्यार्पण कर नमन किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के माध्यम से सत्य, करुणा समानता और मानवता के आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाया। उनके महान विचार और शिक्षाएं आज भी समाज को सदाचार, सामाजिक समरसता और लोककल्याण के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का जीवन और उनके आदर्श हमें समाज में प्रेम, सद्भाव और समानता की भावना को मजबूत करने का संदेश देते हैं। उनके विचारों को आत्मसात कर एक समरस एवं सशक्त समाज के निर्माण में योगदान देना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत, डॉ बबीता सहोत्रा, भावना चौधरी, सतेंद्र नाथ सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

अभिनेत्री उर्मिला सनावर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में

संवाददाता
देहरादून। हरिद्वार में पांच करोड़ रुपये की कथित रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अभिनेत्री उर्मिला सनावर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी की शिकायत पर दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार अभिनेत्री को न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और रविदास धाम की संपत्ति अपने नाम कराने का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, अभिनेत्री उर्मिला सनावर द्वारा रविदास धाम से जुड़ी संपत्ति अपने नाम कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। आरोप है कि संपत्ति से जुड़े इस विवाद के दौरान पांच करोड़ रुपये की मांग भी की गई। पूर्व विधायक की बेटी ने अपनी शिकायत में

फोन भी बरामद किया गया है। बरामद मोबाइल फोन को मामले की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है।

गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अभिनेत्री को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने उर्मिला सनावर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। न्यायालय के इस आदेश के बाद अभिनेत्री को न्यायिक हिरासत में रहना होगा।

गैर इरादतन हत्या में दो गिरफ्तार

हमारे संवाददाता देहरादून। गैर इरादतन हत्या के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने मृतक के साथ मारपीट क उससे पैसे छीनने का प्रयास किया था।

जानकारी के अनुसार बीती 20 अक्टूबर को कोतवाली पटेल नगर को सेवला खुर्द क्षेत्र में राजा रानी वेडिंग पॉइंट के पास सड़क किनारे एक व्यक्ति के अचेत अवस्था मे पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना पर कोतवाली पटेल नगर से पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर उक्त व्यक्ति को उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। मृतक के कपड़ों की तलाशी में उसके पास से पहचान संबंधित कोई भी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ, जिस पर मृतक के शव को 72 घंटे के लिए मोर्चरी में रखवाते हुए उसकी शिनाख्त के प्रयास किये गए। निर्धारित अवधि के पश्चात भी मृतक की पहचान ना हो पाने पर पुलिस द्वारा बाद पीएम (पोस्टमार्टम) शव का अंतिम संस्कार किया गया। मृतक की शिनाख्त हेतु किये जा रहे प्रयासों के दौरान आसपास के लोगों से पूछताछ व मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चैक करने पर सीसीटीवी फुटेज में मृतक के पीछे 2



अन्य व्यक्ति मौके से जाते हुए तथा उनमें से एक व्यक्ति अचानक मृतक के साथ मारपीट कर उसे सड़क पर धक्का देता हुआ दिखाई दिया, मृतक के नीचे गिरने के बाद दोनों व्यक्ति मौके से जाते हुए तथा कुछ देर बाद वापस आकर मृतक को हिलाकर चेक करते हुए भी दिखाई दिए। उक्त व्यक्तियों द्वारा मृतक व्यक्ति के साथ मारपीट कर उसे धक्का दिया गया, जिससे उसके अंदरूनी चोट आई जिससे उसकी मृत्यु हो गई तथा मृत्यु की जानकारी होने पर दोनों व्यक्ति मौके से फरार हो गए। घटना की गंभीरता के दृष्टिगत पुलिस द्वारा स्वयं वादी बनते हुए पुलिस द्वारा खुद की तरफ से उक्त घटना मै सिलपित दोनों अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया। मामले में जाच के दौरान घटना में शामिल आरोपियों के संबंध में जानकारी एकत्रित की गयी तथा प्राप्त जानकारी के आधार पर व मुखबिर की सूचना पर घटना में शामिल दोनों आरोपियों को

पटेल नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम अशरफ उर्फ काला पुत्र असगर निवासी ब्राह्मणवाला, थाना पटेलनगर, देहरादून व सफदर पुत्र अकबर निवासी जीवनगढ़, थाना विकास नगर जनपद देहरादून हाल किराएदार ब्राह्मणवाला, थाना पटेलनगर, देहरादून बताया। बताया कि वह दोनों नशे के आदी हैं तथा शराब के ठेके के आसपास घूमते हुए अत्यधिक नशे में जा रहे व्यक्तियों को चिन्हित कर उनका पीछा करते हैं तथा सुनसान स्थान देखकर उनसे पैसे व अन्य सामान छीन लेते हैं। बताया कि 19 अक्टूबर की रात में वह दोनों आईएसबीटी क्षेत्र में शराब के ठेके के पास घूम रहे थे, इस दौरान उन्हें उक्त व्यक्ति अत्यधिक शराब के नशे में जाता हुआ दिखाई दिया, जिसका उनके द्वारा पीछा करते हुए सेवला खुर्द क्षेत्र में सुनसान स्थान पर उसके साथ मारपीट कर पैसे छीनने का प्रयास किया गया। मारपीट के दौरान उनके द्वारा धक्का देने से वह व्यक्ति सड़क पर गिर कर बेहोश हो गया, जिस पर दोनों मौके से भाग गए तथा कुछ देर बाद उनके द्वारा दोबारा वापस आकर उक्त व्यक्ति को चेक किया गया तो उसकी मृत्यु हो चुकी है, जिस पर दोनों व्यक्ति घबराकर मौके से फरार हो गए।

राहुल गांधी के काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकराईं

हमारे संवाददाता लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सुल्तानपुर न्यायालय में पेशी के लिए आने के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उनके काफिले की कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, यह घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सुल्तानपुर जाते समय हुई।

जानकारी के मुताबिक, पीछे से टक्कर लगने के बाद एक के बाद एक कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। हादसे में कुछ लोगों को हल्की चोटें आने की सूचना है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की

एमपी-एमएलए विशेष अदालत में पेशी के लिए आ रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, वाहनों के बीच टक्कर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 89.5



किलोमीटर के माइलस्टोन के पास हुई। यह स्थान सुल्तानपुर जिले के हलियापुर थाना क्षेत्र में पड़ता है। बताया गया है कि राहुल गांधी के वाहन के पीछे चल रही गाड़ियों के बीच अचानक टक्कर हो गई। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि दुर्घटना किस वजह से हुई और सबसे पहले किन वाहनों के बीच टक्कर हुई थी। राहुल गांधी सुल्तानपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत में वर्ष 2018 के आपराधिक मानहानि मामले से संबंधित कार्यवाही के सिलसिले में जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक, वह सुबह करीब सात बजे अपने आवास से सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए थे। इसी यात्रा के दौरान लखनऊ से सुल्तानपुर जाते समय उनके काफिले के पीछे चल रहे वाहनों के आपस में टकराने की घटना सामने आई।

यूपी में आरएसएस नेता समेत परिवार के 3 लोगों की हत्या

संवाददाता लखनऊ। आदतगंज इलाके में सोमवार सुबह गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुआ विवाद तिहरे हत्याकांड में बदल गया। नौबस्ता के ब्राह्मणी टोला में पड़ोसी ऋषभ शुक्ला पर आरएसएस नेता शिवाजी तिवारी, उनके भाई शिवेंद्र तिवारी और बेटे सुयश तिवारी को गोली मारने का आरोप है। घटना में तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर वारदात में इस्तेमाल पिस्टल बरामद कर ली है।

जानकारी के मुताबिक शिवाजी तिवारी (65) अपने भाई शिवेंद्र तिवारी (55), बेटे सुयश और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते थे। सोमवार सुबह घर के सामने मंदिर के पास गाड़ी खड़ी करने को लेकर उनका पड़ोसी ऋषभ शुक्ला से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर ऋषभ घर से पिस्टल लाया और फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से शिवाजी और सुयश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिवेंद्र ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। आरोपी ऋषभ शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे नेवी का जवान बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक दोनों परिवारों के बीच पहले से विवाद चल रहा था।



कैंटर की टक्कर से दो युवकों की मौत

हमारे संवाददाता नैनीताल। बरेली रोड पर बीती रात पुराने सुभाष नगर पुलिस चेक पोस्ट के पास तेज रफ्तार कैंटर की टक्कर से स्कूटी सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं, लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात व्यवस्था और अधूरे फोरलेन निर्माण को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुक्तिधाम से नगला बाईपास तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर फोरलेन का निर्माण नहीं होने से मार्ग संकरा बना हुआ है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, स्कूटी

सवार दोनों युवक नगला से लालकुआं की ओर आ रहे थे। इसी दौरान पुराने सुभाष नगर पुलिस चेक पोस्ट के पास लालकुआं से रुद्रपुर की ओर जा रहे कैंटर ने उनकी स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी करीब 12 फीट दूर जा गिरी। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें तत्काल हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। लालकुआं कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक दीपक बिष्ट के अनुसार, मृतकों की पहचान 21 वर्षीय चेतन बिष्ट पुत्र स्वर्गीय मोहन सिंह बिष्ट,

निवासी मानपुर पश्चिम, दौलतपुर, गौलापार तथा 24 वर्षीय दीक्षित बिष्ट पुत्र किशन सिंह, निवासी भवाली के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार, मुक्तिधाम से लेकर नगला बाईपास तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर फोरलेन का निर्माण नहीं होने के कारण वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। संकरे मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने से अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। वहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की तेज रफ्तार के चलते दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। लोगों का कहना है कि इस महत्वपूर्ण मार्ग पर यातायात का दबाव देखते हुए फोरलेन निर्माण की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है।

छात्राओं से छेड़छाड़ और धमकी देने के आरोप में दो गिरफ्तार

हमारे संवाददाता उधमसिंहनगर। दिनेशपुर क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान की छह छात्राओं से कथित छेड़छाड़, अश्लील टिप्पणियां करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि छात्राओं के नाम, पते, मोबाइल नंबर और फोटो जैसी निजी जानकारी साझा कर उन्हें निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक, मामले का मुख्य आरोपी अनस नेपाल भागने की फिराक में था, जिसे बनबसा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। दूसरे आरोपी की पहचान मो. बिलाल के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं।

जानकारी के अनुसार, 23 अक्टूबर



2026 को मामला सामने आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति के निर्देश पर दिनेशपुर थाना पुलिस की तीन टीमों गठित की गई। पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की विवेचना एक महिला पुलिस अधिकारी को सौंपी गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी मो. बिलाल, जो संबंधित शिक्षण संस्थान का छात्र बताया जा

रहा है, ने छह छात्राओं के नाम, पते, मोबाइल नंबर और फोटो जैसी निजी जानकारी अपने साथी अनस के साथ साझा की थी। आरोप है कि इसके बाद छात्राओं को अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियों, गाली-गलौज तथा छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। शिकायत में छात्राओं को गला काटने और तेजाब फेंकने जैसी गंभीर धमकियां देने के आरोप भी लगाए गए हैं। इसके अलावा, शिकायत करने पर पीड़ित पक्ष को धमकाने की बात भी सामने आई है। पुलिस इन सभी आरोपों की जांच कर रही है।

पुलिस के मुताबिक, मुख्य आरोपी अनस गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल की ओर भागने की कोशिश कर रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे बनबसा

क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। वहीं, दूसरे आरोपी मो. बिलाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों की पहचान अनस पुत्र मोहम्मद मोबिन, उम्र 22 वर्ष, निवासी बिसरख क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और मो. बिलाल पुत्र मोहम्मद यूसुफ, उम्र 20 वर्ष, निवासी खेमपुर, जिला रामपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मामले से संबंधित दोनों मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अब इन मोबाइल फोन में मौजूद डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि छात्राओं की निजी जानकारी कहां से प्राप्त की गई, इसे किन लोगों के साथ साझा किया गया और क्या इस मामले में अन्य लोग भी शामिल हैं।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटेर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, एडवोकेट
बैजनाथ, एडवोकेट

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्रियों के लिए प्रिंटेर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।